सोमवार, 20 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

पीवी सिंधु ने अकाने यामागुची को हराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

ME TOO बाद बदल गए बाबूजी

Page-05

भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ लगातार भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की। राजौरी ज़िले में अचानक आई बाढ़ के बाद, शाह ने इमरजेंसी राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संपर्क किया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राजौरी के मुरादपुर इलाके में तेज़ी से बढ़ते पानी के स्तर के कारण फँसे दो लोगों को इमरजेंसी रेस्पॉन्डर ने सफलतापूर्वक बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने कहा कि भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में फँसने के बाद, राजौरी के मुरादपुर में नदी से दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाव दलों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। ज़िला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। अभिषेक शर्मा ने कहा कि अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी सलाह का पालन करें और जब तक मौसम और बाढ़ की स्थिति में सुधार न हो, तब तक गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें।

सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंचीं हाई कोर्ट

निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और जलवायु संरक्षण अभियान से जुड़े सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर वांगचुक को अपनी पसंद के किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और उपचार प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से परिवार को दी गई जानकारी और सार्वजनिक हेल्थ बुलेटिन में अंतर है।गीतांजलि आंग्मो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अब उनका सफदरजंग अस्पताल पर से भरोसा उठ चुका है। उनके अनुसार, अस्पताल ने परिवार को बताया था कि सोनम वांगचुक का पोटैशियम स्तर गिरकर 2.9 तक पहुंच गया है, जिसे डॉक्टरों ने बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति बताया। लेकिन बाद में जारी सार्वजनिक हेल्थ बुलेटिन में इस स्तर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया और केवल इतना कहा गया कि पोटैशियम का स्तर कम हुआ है।आंग्मो का दावा है कि परिवार ने स्वतंत्र लैब से जांच कराई, जिसमें पोटैशियम स्तर 3.5 पाया गया, जो सामान्य सीमा के भीतर माना जाता है। उनका आरोप है कि अस्पताल ने वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ साझा नहीं किया, जिससे परिवार की चिंताएं और बढ़ गई हैं।उन्होंने यह भी कहा कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज करने या उन्हें किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण परिवार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में हाई कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की गई है ताकि उनकी सेहत और अधिक खराब होने से पहले उचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।गीतांजलि आंग्मो ने अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अस्पताल की मंजिल पर करीब 30 और पूरे परिसर में 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिससे परिवार की आवाजाही सीमित हो गई है। उन्होंने इसे सामान्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं बल्कि "गैर-कानूनी हिरासत" जैसा माहौल बताया। अब इस मामले में सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है या नहीं, साथ ही अस्पताल और प्रशासन पर लगाए गए आरोपों की भी न्यायिक जांच हो सकती है।अब इस मामले में सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है या नहीं, साथ ही अस्पताल और प्रशासन पर लगाए गए आरोपों की भी न्यायिक जांच हो सकती है।

मुख्यमंत्री विजय का भ्रष्टाचार पर 'ज़ीरो टॉलरेंस' एक्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को तब और तेज़ी मिली, जब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और कथित भ्रष्टाचार व बिना हिसाब-किताब वाले वित्तीय लेन-देन के लिए उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। यह कार्रवाई पिछले हफ़्ते चेन्नई के दो ज़ोन में की गई अचानक जांच के बाद हुई, जिसमें अधिकारियों को कथित तौर पर बिना हिसाब-किताब वाला कैश और संदिग्ध डिजिटल लेन-देन मिले। GCC अधिकारियों के अनुसार, यह जांच ज़ोन 6 और 9 में की गई, जिसमें उत्तरी और मध्य चेन्नई के कई अहम इलाके शामिल थे। GCC के एक सीनियर अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि अचानक की गई जांच के दौरान, एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ₹2.39 लाख के GPay ट्रांज़ैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को तमिलनाडु के विजिलेंस और एंटी-करप्शन डायरेक्टरेट (DVAC) से रिपोर्ट मिलने के बाद सस्पेंशन और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों पर भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। ज़ोन 6 में कोलाथुर, अयनवरम और पेराम्बुर जैसे इलाके आते हैं, जबकि ज़ोन 9 में सेंट्रल चेन्नई के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिनमें थाउज़ेंड लाइट्स, माइलापोर और नुंगमबक्कम आते हैं।

परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस ने किया समर्थन की खबरों का खंडन

संसद के मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद, फर्जी और "प्लांटेड" करार देते हुए सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ टीवी चैनल जानबूझकर ऐसी खबरें चला रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वदलीय बैठक में परिसीमन विधेयक के समर्थन का कोई सवाल ही नहीं उठा और इस तरह की खबरें केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश हैं। कांग्रेस ने दोहराया कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई समर्थन नहीं दिया है।दरअसल, केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान

संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और सरकार के विधायी एजेंडे पर विभिन्न दलों से चर्चा करना था।हालांकि बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने कुछ मिनटों के लिए सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) को बैठक में आमंत्रित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना था कि इस पार्टी की वैधानिक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसे सर्वदलीय बैठक में बुलाना उचित नहीं था। विरोध दर्ज कराने के बाद सभी विपक्षी दल दोबारा बैठक में लौट आए और चर्चा में शामिल हुए।जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि NCPI उन 20 बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसदों के लिए एक "पार्किंग प्लेस" बन गई है, जिनकी सदस्यता और दल-बदल से जुड़े मामलों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अंतिम फैसला अभी लंबित है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक स्पीकर इस मामले में निर्णय नहीं लेते, तब तक N C P I को औपचारिक राजनीतिक पहचान देकर सरकारी बैठकों में शामिल करना संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

संसद सत्र से पहले NCPI पर सियासी घमासान

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (इंडिया) (NCPI) को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला। बैठक के दौरान बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसदों ने NCPI को औपचारिक मान्यता देने की मांग उठाई, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने का विरोध करते हुए कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। इस घटनाक्रम ने संसद सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल को गर्म कर दिया है।बागी टीएमसी सांसद और वरिष्ठ नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि NCPI अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है। उनका दावा था कि पार्टी के पास तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) से भी अधिक सांसद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें NCPI को औपचारिक मान्यता देने और उसके संसदीय दर्जे को स्वीकार करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पत्र सांसद काकोली घोष दस्तीदार के माध्यम से स्पीकर को सौंपा जाएगा।

राज्य का दर्जा बहाली की मांग पर दिल्ली में NC का प्रदर्शन, फारूक अब्दुल्ला करेंगे नेतृत्व

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पहले इस प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करने वाले थे, लेकिन जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिलों में अचानक आई भीषण बाढ़ और जनहानि के कारण उन्होंने अपना दिल्ली दौरा बीच में ही समाप्त कर जम्मू लौटने का फैसला किया। अब पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी और जम्मू संभाग में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए उनका प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। उमर ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और उसकी अगुवाई फारूक अब्दुल्ला करेंगे।उधर, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने इस फैसले पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि "पिता दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और बेटा जम्मू में अच्छा बच्चा बनकर रहेगा।" लोन की इस टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई।नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी तनवीर सादिक ने सज्जाद लोन के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब लोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में अपने परिजनों को खो चुके हों, तब मुख्यमंत्री का उनके बीच जाकर राहत कार्यों की निगरानी करना राजनीति नहीं, बल्कि उनकी संवैधानिक और मानवीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल कराने की लड़ाई पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है और यह संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन आपदा के समय पीड़ितों के साथ खड़ा होना भी सरकार का पहला दायित्व है।नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत देशभर के 56 विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक दिल्ली प्रशासन से प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र और विपक्ष के बीच प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बनने की संभावना है।

अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर लगातार आठवें दिन अमेरिकी हवाई हमले

जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान समर्थित ठिकानों पर लगातार आठवें दिन भी हवाई हमले किए। इस घटनाक्रम ने पूरे मध्य-पूर्व में बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका बढ़ा दी है और वैश्विक समुदाय की चिंता भी गहरा गई है।

मध्य-पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 जुलाई को अमेरिकी सेना ने लगातार आठवीं रात ईरान समर्थित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। यह कार्रवाई उस हमले के जवाब में की गई है, जिसमें जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और पूरे मध्य-पूर्व में युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका बढ़ गई है।अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के अनुसार, हवाई हमलों का लक्ष्य ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के हथियार भंडार, कमांड सेंटर और सैन्य ठिकाने थे। अमेरिका का कहना है कि वह अपने सैनिकों पर हुए हमले का जवाब देने और क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई और तेज की जाएगी।दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के इन हमलों की कड़ी निंदा की है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है और उसकी सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके हितों या सहयोगी समूहों पर हमले जारी रहे तो वह भी उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान समर्थित संगठनों ने भी अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर केवल मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। कई यूरोपीय देशों ने भी दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है।विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह सैन्य टकराव वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। यदि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मध्य-पूर्व के घटनाक्रम पर टिकी है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि दोनों देश कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं या फिर यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेता है।

पेरू में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही, कई लोगों की मौत

दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 19 जुलाई को आए शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक तबाही मचा दी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई, जिसके झटके राजधानी लीमा सहित देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप के कारण कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, सड़कें टूट गईं और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रारंभिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम छह लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।पेरू के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में समुद्र के भीतर था। तेज झटकों के कारण लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कई स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक भवनों को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे कई प्रमुख सड़क मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गए।भूकंप के तुरंत बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय कर दिया। सेना, पुलिस, अग्निशमन विभाग और राहत एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं, जबकि घायलों का इलाज अस्थायी चिकित्सा शिविरों और अस्पतालों में किया जा रहा है। कई स्थानों पर बिजली और संचार सेवाओं को बहाल करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और पेरू की भूवैज्ञानिक एजेंसियां लगातार आफ्टरशॉक्स पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल सुनामी का कोई बड़ा खतरा नहीं बताया गया है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में एहतियात बरता जा रहा है।

भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया

भारत में मॉनसून जोर पकड़ेगा,40 से 30 डिग्री पर आएगा पारा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का अनुमान लगाया है और संवेदनशील इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और अचानक बाढ़ (flash flood) का खतरा होने की चेतावनी दी है। गर्मी और उमस भरे वीकेंड के बाद दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट की उम्मीद है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मॉनसून के जोर पकड़ने के साथ, राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान रविवार के लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर मंगलवार तक लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है। दिल्ली में सोमवार से बुधवार के बीच कहीं-कहीं आंधी-तूफान और भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे दिन का तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस के निचले स्तर पर आ जाएगा। IMD ने दिल्ली के लिए तापमान का अनुमान जारी किया है: रविवार को 40 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 37 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 33 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 32 डिग्री सेल्सियस। रविवार को राजधानी में कहीं-कहीं बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 20–30 किमी/घंटा की तेज़ ज़मीनी हवाएं चलने की संभावना है। नेशनल कैपिटल रीजन (N C R) में, गाज़ियाबाद में न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि गुरुग्राम में तापमान 34 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। फरीदाबाद में मौसम के अपेक्षाकृत ठंडा रहने और तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

कीव समेत कई शहर निशाने पर जवाब में यूक्रेन ने ड्रोन से किया पलटवार

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 19 जुलाई को रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, रातभर चले हमलों में कई रिहायशी इमारतों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और परिवहन ढांचे को निशाना बनाया गया। हमलों के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि अनेक नागरिक घायल हुए और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने रूस द्वारा दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। राजधानी कीव सहित कई शहरों में देर रात तक एयर रेड सायरन बजते रहे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया और क्षतिग्रस्त इलाकों में आपातकालीन सेवाएं तैनात कर दी गईं।रूस की ओर से कहा गया कि यह हमला यूक्रेन के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। मॉस्को का दावा है कि हाल के दिनों में यूक्रेन द्वारा रूसी सीमा के भीतर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि रूस ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाने के आरोपों को खारिज किया है।दूसरी ओर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के कई सैन्य लॉजिस्टिक केंद्रों और ईंधन डिपो पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसका उद्देश्य रूसी सेना की आपूर्ति व्यवस्था को कमजोर करना है। इस जवाबी कार्रवाई के बाद रूस के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि लगातार बढ़ रहे हमले न केवल मानवीय संकट को और गंभीर बना रहे हैं, बल्कि किसी भी कूटनीतिक समाधान की संभावना को भी कमजोर कर रहे हैं।

गुयाना के तट पर यात्री नौका हादसा, दर्जनों लोग लापता

दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में 19 जुलाई को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। देश के उत्तरी तटीय क्षेत्र के पास यात्रियों से भरी एक नौका अचानक समुद्र में पलट गई, जिसके बाद कई लोग लापता हो गए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, नौका में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और खराब मौसम के कारण संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तटरक्षक बल ने तुरंत बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया।गुयाना की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक दुर्घटना की सूचना मिलते ही नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरों की सहायता से संयुक्त खोज अभियान शुरू किया गया। कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गोताखोरों और हेलीकॉप्टरों की मदद से समुद्र में लगातार तलाश अभियान चलाया जा रहा है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय समुद्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ रही थीं। आशंका है कि मौसम खराब होने के बावजूद नौका ने यात्रा शुरू की, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि क्या नौका में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया था और क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था।गुयाना के राष्ट्रपति ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने राहत एजेंसियों को निर्देश दिया है कि लापता लोगों की तलाश में कोई कमी न छोड़ी जाए और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।इस हादसे के बाद पूरे देश में समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी यात्री नौकाओं में सुरक्षा उपकरणों की कमी, क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना और खराब मौसम में संचालन जैसी लापरवाहियां ऐसे हादसों की प्रमुख वजह बनती हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर राहत एवं बचाव अभियान पर टिकी है और प्रशासन को उम्मीद है कि लापता लोगों का जल्द पता लगाया जा सकेगा।

संपादक की कलम से

पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसके बिना मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण की कल्पना भी संभव नहीं है। विडंबना यह है कि जिस जल को प्रकृति ने अमूल्य धरोहर के रूप में हमें सौंपा है, उसी का सबसे अधिक दुरुपयोग भी हम ही कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में हर वर्ष गर्मियों के दौरान जल संकट गंभीर रूप ले लेता है। कहीं पेयजल के लिए लंबी कतारें लगती हैं तो कहीं किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसलें बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि यदि अभी भी जल संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल हो सकता है।भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल है, जबकि मीठे जल के संसाधन सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित शहरीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, नदियों का प्रदूषण और वर्षा जल के उचित संचयन की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। अनेक शहरों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई नदियां औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरे के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 'जल जीवन मिशन', 'अटल भूजल योजना' और वर्षा जल संचयन जैसी पहलें सकारात्मक दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कई राज्यों में तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि, केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे इस चुनौती का समाधान संभव नहीं है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति जल संरक्षण को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं मानेगा, तब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। हर नागरिक अपने स्तर पर छोटे-छोटे प्रयास करके बड़ा बदलाव ला सकता है। घरों में पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को अपनाना, रिसाव वाले नलों की मरम्मत कराना, पेड़ों का संरक्षण और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना ऐसे कदम हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। कृषि क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर भी पानी की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है।विद्यालयों और महाविद्यालयों में जल संरक्षण को व्यवहारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी बचपन से ही इस विषय के प्रति संवेदनशील बने। मीडिया, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन को भी जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पानी के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जल संकट केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का भी प्रश्न है।

मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में हंगामा विपक्ष का वॉकआउट; संसद से पहले सियासी पारा चढ़ा

21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ताकि सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सभी दलों से चर्चा की जा सके। लेकिन बैठक में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को बुलाए जाने को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। इसी विवाद के चलते बैठक में हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने कुछ समय के लिए वॉकआउट कर दिया, जिससे संसद सत्र से पहले ही सियासी माहौल गरमा गया।

संसद के मानसून सत्र की शुरूआत से ठीक पहले 19 जुलाई को आयोजित सर्वदलीय बैठक में उस समय राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया, जब विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को बैठक में आमंत्रित किए जाने का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। इस घटनाक्रम ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन सांसदों की पार्टी सदस्यता और राजनीतिक स्थिति को लेकर विवाद चल रहा है, उन्हें आधिकारिक सर्वदलीय बैठक में बुलाना लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है।बैठक के दौरान इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि बैठक से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ समय बाद बातचीत के बाद विपक्ष के नेता दोबारा बैठक में लौटे और आगे की कार्यवाही में शामिल हुए।सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद में स्वस्थ बहस लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन लगातार हंगामा और कार्यवाही बाधित करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। सरकार ने संकेत दिया कि मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक, आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव और जनहित के मुद्दे सदन में पेश किए जाएंगे।दूसरी ओर विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस सत्र में सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुका है। विपक्षी दलों ने परिसीमन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, विभिन्न राज्यों में कानून-व्यवस्था, राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले की जांच और अन्य राजनीतिक विषयों पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही है। विपक्ष का कहना है कि संसद जनता की आवाज उठाने का सर्वोच्च मंच है और सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सर्वदलीय बैठक में हुआ यह टकराव केवल शुरुआत है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में सदन के भीतर तीखी बहस, जोरदार विरोध और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र पर है, जहां सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष जनहित और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा।

राम मंदिर दान मामले पर राहुल गांधी-खड़गे का पीएम मोदी को पत्र

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी कथित दान राशि में अनियमितता के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। 19 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी तरह का संदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था और धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।अपने पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि यदि दान राशि के प्रबंधन और उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, ताकि किसी भी पक्ष पर पक्षपात का आरोप न लगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी धार्मिक संस्था या श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि दान में दिए गए धन के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पार्टी ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में भी जोरदार तरीके से उठाएगी और सरकार से विस्तृत जवाब मांगेगी।वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष बिना अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार किए केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी दोहराया कि मंदिर निर्माण और दान राशि का पूरा लेखा-जोखा नियमानुसार रखा गया है तथा सभी वित्तीय प्रक्रियाएं ऑडिट के दायरे में हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा यह मुद्दा उठाना सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर भाजपा इसे आस्था के विषय पर राजनीति करने का प्रयास बता रही है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर दान प्रकरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी।

अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली राहत ऑफिस को गिराने पर रोक

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को रविवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में उनके ऑफिस को गिराने पर रोक लगा दी और सभी पक्षों को अगली सुनवाई या जुलाई के आखिर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस राजा बसु चौधरी ने दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को अमतला में अभिषेक के ऑफिस से जुड़े सभी दस्तावेज़ जमा करने का भी निर्देश दिया। बताया जाता है कि यह ऑफिस 'लीप्स एंड बाउंड्स' कंपनी का है। बताया जा रहा है कि इस इमारत का स्वामित्व 'लीप्स एंड बाउंड्स' कंपनी के पास है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, तृणमूल नेता अभिषेक 'लीप्स एंड बाउंड्स' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। अदालत ने डायमंड हार्बर रोड स्थित इमारत को तोड़े जाने की कार्रवाई पर जुलाई के अंत तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। उसने कहा कि इस मामले की नियमित पीठ के समक्ष दोबारा सुनवाई की जाएगी। 'लीप्स एंड बाउंड्स' ने इमारत को गिराए जाने की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने अभिषेक के अमतला स्थित कार्यालय को तोड़ने की कार्रवाई शनिवार को शुरू की थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन का कहना है कि यह इमारत कथित तौर पर स्वीकृत भवन योजना के बिना और लागू नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई थी। अभिषेक ने इमारत को अपना निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय बताते हुए शनिवार को दावा किया था कि अमतला स्थित उनका कार्यालय खरीदी गई जमीन पर कानूनी रूप से बनाया गया है और इसके लिए सभी जरूरी अनुमतियां भी ली गई थीं।

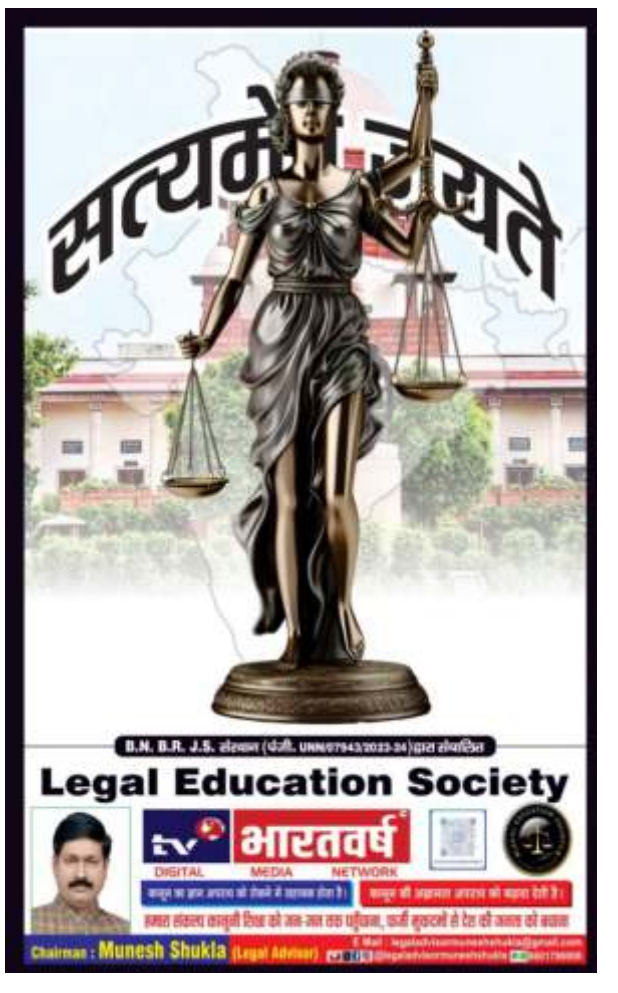

यूके की फास्ट-ट्रैक मास्टर्स डिग्री: किसे मिलेगा फायदा, किसे हो सकता है नुकसान?

अगर आप ब्रिटेन में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने यहां मास्टर्स डिग्री को लेकर एक दिलचस्प चीज देखी होगी। ब्रिटेन में एक साल के भीतर ही मास्टर्स डिग्री मिल जाती है, जबकि अगर कोई अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पढ़ने जाए, तो उसे दो साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। इस वजह से छात्रों के साथ-साथ पैरेंट्स के मन में भी ये सवाल उठने लगता है, 'क्या एक साल की मास्टर डिग्री सच में काफी है? या यह कुछ भी ठीक से सीखने के लिए बहुत कम समय है?' दरअसल, ब्रिटेन में अंडरग्रेजुएट कोर्स में मुख्य सब्जेक्ट्स को गहराई के साथ पढ़ाया जाता है, जिस वजह से मास्टर्स में कई सारे टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रिटेन में मास्टर्स करने के दौरान बिना रुके ही पढ़ाई करनी पड़ती है। क्लास, असाइनमेंट, एग्जाम और फिर एक फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सभी आमतौर पर 12 महीनों में पूरे हो जाता है। स्टूडेंट्स को कोई ब्रेक भी नहीं मिलता है। इस तरह स्टूडेंट्स को सारी जरूरी चीजें एक साथ जल्दी-जल्दी पढ़ा दी जाती हैं, ताकि वे जॉब के लिए तैयार हो सकें। भारतीयों के लिए तो इनकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। एक वर्षीय मास्टर्स के निम्नलिखित नुकसान हैं।

कम समय: क्लास की शुरुआत तुरंत हो जाती है और फिर कुछ ही महीनों में रिसर्च जमा करने की भी तारीख आ जाती है। इस वजह से इंटर्नशिप, पार्ट-टाइम प्रोजेक्ट्स और अलग-अलग स्पेशलाइजेशन करने के लिए समय नहीं मिलता है।

इंटर्नशिप के कम मौके: दो साल के कोर्स में, स्टूडेंट्स को अक्सर पहले और दूसरे साल के बीच समर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। ब्रिटेन में एक वर्षीय कोर्स में ज्यादा समय नहीं मिल पाता है।

नेटवर्किंग के लिए कम समय: प्रोफेसर, अल्युमिनी और बाकी के छात्रों के साथ नेटवर्किंग के लिए समय चाहिए, लेकिन एक वर्षीय कोर्स में इसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इसका असर जॉब के दौरान देखने को मिलता है।

थकान महसूस होना: बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रिटेन में एक वर्षीय मास्टर्स के दौरान थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारा कोर्स काफी जल्दी हो रहा है, जिस वजह से पढ़ाई थकान भरी लगने लगती है।

जॉब में दिक्कत: कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, जो 2 वर्षीय मास्टर्स डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स को ही नौकरी देने में प्राथमिकता देती हैं। इस वजह से 1 वर्षीय मास्टर्स डिग्री होकर भी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको समय और पैसा बचाना है, तो फिर आपके लिए एक वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम बिल्कुल फिट है। वर्क एक्सपीरयंस और करियर गोल की जानकारी रखने वाले स्टूडेंट्स भी ब्रिटेन में एक वर्षीय मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी से खत्म होने वाले कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डिग्री पूरी कर तुरंत जॉब करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए फिट होगा। अगर आपकी दिलचस्पी स्पेशलाइजेशन में है, तो फिर आपको ब्रिटेन के एक वर्षीय प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें इंटर्नशिप जरूरी है, तो फिर एडमिशन लेने से बचें, क्योंकि आपके पास इसे पूरा करने के लिए समय नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको धीरे-धीरे पढ़ाई करनी है या फिर बैचलर्स के तुरंत बाद मास्टर्स करना है, तो एडमिशन लेने से बचें।

संघर्ष से सफलता तक का सफर, नाइट वॉचमैन का जज्बा बना मिसाल

अरुणाचल प्रदेश की पटकई की दुर्गम पहाड़ियों में वांचो समुदाय की चर्चा आज देशभर में है। क्योंकि उनका समुदाय का लड़का आज भारतीय फौज में मेजर बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वांचो परिवार के लिए विपरीत हालातों से लड़कर यह मुकाम हासिल किया है। मेजर लाइचैट पॉल वांगपान की सक्सेस स्टोरी हजारों-लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। देश आज उनके संघर्ष, मेहनत और कामयाबी को सलाम कर रहा है। मेजर लाइचैट पॉल वांगपान अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के लोंगफोंग गांव के बेहद गरीब परिवार से आते हैं। कुछ साल तक यहां के लोग बांस, लकड़ी और पत्तियों से बने घरों में रहते थे। बिजली-पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि, हाल के वर्षों में चीजें बेहतर हो रही हैं। गरीबी ने वांगपान को बहुत छोटी-सी उम्र में जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा था ताकि परिवार का सहारा बन सकें। जिंदगी मुश्किल थी और मौके कम थे, लेकिन हार मानना कभी कोई ऑप्शन नहीं था। घर का खर्च चलाने के लिए वांगपान ने नाइट वॉचमैन का काम किया। वे सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में नाइट वॉचमैन थे।

किलियन एमबाप्पे ने विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 22 गोल का नया कीर्तिमान स्थापित किया

पीवी सिंधु ने अकाने यामागुची को हराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपनी शानदार वापसी का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। सिंधु ने रविवार को जापान ओपन के फाइनल में घरेलू खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेम में हराकर पहली बार इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ वह जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। बता दें कि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से मात दी। यह सिंधु का पहला सुपर 750 स्तर का खिताब भी है। इस जीत ने उनके दो साल से ज्यादा समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म कर दिया। गौरतलब है कि सिंधु का इससे पहले बड़ा खिताब वर्ष 2019 में आया था, जब उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने 2024 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन जापान ओपन की जीत उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गई है। फाइनल मुकाबले में सिंधु शुरुआत से ही आत्मविश्वास में नजर आईं। उन्होंने अपने मजबूत नेट खेल का शानदार इस्तेमाल किया और कई मौकों पर यामागुची को ऊंचे शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने क्रॉस कोर्ट स्मैश और तेज शॉट्स की मदद से लगातार अंक हासिल किए। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शुरुआती दौर में स्कोर बराबरी पर रहा, लेकिन सिंधु ने 8-6 की बढ़त बनाई। यामागुची ने वापसी करते हुए बढ़त हासिल की, लेकिन सिंधु ने लंबी रैलियों में धैर्य दिखाया और 11-11 की बराबरी के बाद मैच पर नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए पहला गेम 21-17 से अपने नाम किया।

कपिल देव ने कहा कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का स्थान 'पक्का' नहीं

महान क्रिकेटर कपिल देव ने कहा है कि भारतीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का भी स्थान कभी 'पक्का' नहीं हो सकता लेकिन जब तक ये अनुभवी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए। रोहित (39 वर्ष) और कोहली (37 वर्ष) अपने शानदार करियर के अंतिम दौर में हैं। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में शुरुआती दो मुकाबलों में रोहित के खराब प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं।कपिल ने यहां "कपिल देव-सुनील गुप्ता अस्पताल" में पीटीआई से बातचीत में कहा, "क्रिकेट में किसी का स्थान कभी भी स्थायी नहीं होता। जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, वही खेलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। मेरा मानना है कि प्रदर्शन पर नजर रखिए और जब तक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उसे खेलने दीजिए।" उन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन का है। कपिल ने कहा, "सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया, तब उनमें काफी क्रिकेट बाकी था। यह फैसला चयनकर्ताओं का काम है। मैं यह नहीं कहूंगा कि किसे बाहर किया जाए। यह चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ टीवी पर मैच देखकर अपनी राय दे सकता हूं।" उन्होंने कहा, "टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं पर भरोसा रखिए कि वे भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चुनेंगे। अगर टीम हारती भी है, तब भी हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए।" उन्होंने कहा, "रोहित अब 20 साल के नहीं हैं। वह लगभग 40 वर्ष के हैं और हर खिलाड़ी को एक दिन संन्यास लेना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को जो खुशी दी है उसके लिए उन्हें सलाम।

रोहित शर्मा ने साफ किया कि उनका लक्ष्य 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना है

रविवार को लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक लगाने के बाद, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल भविष्य को लेकर चल रही लगातार अफ़वाहों को साफ़ तौर पर खारिज कर दिया और अपने आलोचकों को कड़ा संदेश दिया। 'होम ऑफ़ क्रिकेट' (लॉर्ड्स) में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनने के बाद बात करते हुए, इस अनुभवी बल्लेबाज़ ने साफ़ कर दिया कि संन्यास लेने का उनका अभी कोई इरादा नहीं है। मैच के बाद BCCI को दिए एक दमदार इंटरव्यू में, रोहित ने बाहर की बातों और अपने खेल पर फोकस करने के बीच साफ़ फ़र्क बताया। शर्मा ने साफ़ कहा कि मेरा काम बल्ले से खेलना है। मैदान पर उतरना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। डेब्यू के समय से ही मुझे यही करने के लिए कहा गया है और मैं यही करता रहूंगा। जब से मैंने डेब्यू किया है, तब से ही ये बातें होती रही हैं। जब तक मैं खेलता रहूंगा, ये बातें होती रहेंगी। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अहम यह है कि मैं मैदान पर कैसा खेलता हूं। मैं टीम की कामयाबी में योगदान देना चाहता हूं। मेरा पूरा ध्यान बस इसी पर है।रोहित के करियर में एक काम अभी अधूरा है — जो अब सिर्फ़ 50-ओवर के फ़ॉर्मेट तक ही सीमित है — और वह है साउथ अफ़्रीका में 2027 का वर्ल्ड कप जीतना। यह एक ऐसा मिशन था जो 19 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद में पूरा नहीं हो सका, जिससे तत्कालीन भारतीय कप्तान लगभग एक महीने तक गुमसुम हो गए थे। T20I से शान से रिटायर होने और बिना किसी खास समारोह के टेस्ट क्रिकेट से हटने के बाद, रोहित ने अपना पूरा ध्यान एक ही फ़ॉर्मेट पर लगा दिया है।

पापा के 50वें बर्थडे पर बेटी का सरप्राइज

बच्चों की खुशी के लिए माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं. अपनी जरूरतों को पीछे रखकर वे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब बच्चे बड़े होकर माता-पिता के लिए कुछ ऐसा कर दें, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी न की हो, तो वह पल बेहद खास बन जाता है. तेलंगाना से ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां एक बेटी ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. ⊙

साइंस से समाज बदलने का जुनून

नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को तबीयत बिगड़ने पर जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है.

सोशल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में चल रही उनकी भूख हड़ताल के बीच शनिवार तड़के उन्हें जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया.

उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में पहुंच चुकी है. इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी सोनम वांगचुक को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई यूजर्स उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं, जबकि जंतर-मंतर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक किसी आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आए हों. लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग से लेकर लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च जैसे मुद्दों को लेकर वह पहले भी चर्चा में रहे हैं. लेकिन आंदोलनों से अलग सोनम वांगचुक की एक और पहचान है, जिसने उन्हें भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में पहचान दिलाई. वह इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और इनोवेटर के तौर पर लंबे समय से हिमालयी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में जुटे रहे हैं. लद्दाख में जन्मे सोनम वांगचुक ने साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL की सह-स्थापना की थी. ⊙

आंदोलन से अलग इनोवेशन भी है पहचान

सोनम वांगचुक के काम में एक बात बार-बार दिखाई देती है- बड़ी समस्याओं के लिए स्थानीय संसाधनों से सरल और कम खर्च वाले समाधान तलाशना. चाहे पहाड़ों में पानी बचाने के लिए आइस स्तूप हो, ठंड से निपटने के लिए पैसिव सोलर इमारतें या फिर छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने का मॉडल, उनकी कोशिशें लद्दाख की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के इर्द-गिर्द विकसित हुई हैं. ⊙

विदेश से लौटकर भारत में काम करना आसान नहीं?

विदेश में कई साल तक काम करने के बाद भारत लौटना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. खासकर तब, जब यहां का वर्क कल्चर विदेश में काम करने के दौरान बनी आदतों से बिल्कुल अलग नजर आए.

एक NRI महिला ने भारत में काम करने के अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. उन्होंने लास्ट मिनट पर मीटिंग कैंसिल होने से लेकर लंबे इंतजार और फीडबैक लेने के तरीके तक कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें वह भारतीय वर्क कल्चर की बड़ी समस्याएं मानती हैं. इंस्टाग्राम यूजर नूपुर दवे ने एक पोस्ट में उन परेशानियों का जिक्र किया, जिनका सामना उनके मुताबिक

विदेश से लौटकर भारत में काम करने वाले NRI को करना पड़ सकता है. उन्होंने इसे 'भारतीय वर्क कल्चर में NRI के सामने आने वाली बड़ी समस्याएं' बताया. नूपुर ने अपने अनुभव के आधार पर दावा किया कि अगर आप किसी प्रभावशाली पद पर नहीं हैं, तो आपकी मीटिंग आखिरी समय में कैंसिल या रीशेड्यूल हो सकती है. ⊙

एयर होस्टेस की ड्रेस में महिला ने किया डांस

हवाई जहाज में सफर के दौरान आमतौर पर यात्री अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन से उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एयर होस्टेस की ड्रेस पहनकर एक महिला अचानक विमान के बीच वाले रास्ते में डांस करने लगी. उसे देखकर पहले यात्री हैरान रह गए.

पहले तो क्रू मेंबर भी कन्फ्यूज हुए, फिर पता चला कि वह फ्लाइट की ही एक पैसेंजर है. इसके बाद फिर माहौल ऐसा बना कि एक और शख्स भी उठकर नाचने लगा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला ब्रिटेन की लो-कॉस्ट एयरलाइन रयानएयर

की एक फ्लाइट का है, जो लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से रवाना हुई थी.

बताया गया कि महिला अपनी शादी से पहले दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी (Hen Do) मनाने छुट्टी पर जा रही थी. वीडियो में दिखता है कि महिला एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहनकर विमान के गलियारे में मस्ती से डांस करने लगती है. वह कभी आगे बढ़ती है, कभी झूमती है और कभी यात्रियों के सामने झुककर डांस करती है.

शुरुआत में लोग उसे हैरानी से देखते रहे, लेकिन कुछ देर बाद माहौल और भी अजीब हो गया. तभी गुलाबी पावर रेंजर की ड्रेस पहने एक शख्स भी अपनी सीट से उठा और महिला के साथ डांस करने लगा. ⊙

'मी टू' के बाद बदल गए 'संस्कारी बाबूजी'

आलोक नाथ हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं. फैंस उन्हें 'संस्कारी बाबूजी' के नाम से जानते हैं, क्योंकि कई बड़ी फिल्मों में वो संस्कारी पिता के रोल में दिखाई दे चुके हैं.

'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन' में आलोक नाथ ने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला. हालांकि, साल 2018 में 'मी टू' मूवमेंट में लगे आरोप के बाद एक्टर सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही दिखाई दिए. 'मी टू' विवाद से एक्टर की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा.

इस बारे में उनके बचपन के दोस्त और एक्टर राजेश पुरी ने सिद्धार्थ कन्नन को किए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मीटू आरोपों

का आलोक पर बहुत गहरा असर हुआ है. इस चीज ने उन्हें पूरी तरह से बदलकर रख दिया है.

राजेश पुरी ने इंटरव्यू में आलोक नाथ के बारे में बात में खुलासा किया कि एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है. उन्होंने यह भी बताया कि आलोक नाथ अब शांति में सुकूनभरी जिंदगी जी रहे हैं. वो अपने घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं.

आलोक नाथ के बारे में बात करते हुए राजेश पुरी ने कहा- जब आलोक नाथ पर 'मी टू' के आरोप लगे थे, तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि उन्हें एक संस्कारी एक्टर के रूप में जाना जाता था. इन आरोपों के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया. वो इंडस्ट्री से लगभग गायब हो चुके हैं. आलोक नाथ के सफर पर बात करते हुए, राजेश पुरी ने माना कि उनके पुराने दोस्त से शायद कुछ गलतियां हुई होंगी. ⊙

NEET पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- 'NEET नहीं, CHEAT परीक्षा'

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर भाजपा सरकार और एनटीए पर निशाना साधा। उन्होंने जवाबदेही की कमी, इस्तीफा न होने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी रिजल्ट गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा में हो रही लगातार धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश ने नीट को चीट करार देते हुए सरकार की जवाबदेही और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि NEET Re-Exam में घपलों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार में न तो किसी की जिम्मेदारी तय की जा रही है और न ही कोई जवाबदेही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में इस्तीफा देना या दिलवाना तो पूरी तरह से असंभव बात हो गई है। अखिलेश ने कहा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कड़वा सच यह है कि संगठन में शीर्ष पर बैठे तथाकथित नैतिक लोग अपने किसी संगी-साथी मंत्री पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर मंत्री खुद को फंसता देखेगा तो वह बाकी सभी भाजपाई हिस्सेदारों के घपलों के दबे-छुपे राज खोल देगा। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि यही हाल भाजपा सरकार के हर मंत्रालय का है और इसी वजह से सत्ता पक्ष में इस्तीफे नहीं होते हैं। उन्होंने जनता की तरफ से सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या मुखबिरी और पेपर लीक में कोई ऐतिहासिक संबंध होता है। अपने पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने कविता की पंक्तियों के जरिए तीखा निशाना साधते हुए लिखा कि, 'छुपे बैठे भ्रष्टाचार की काली कोठरी में, भाजपाई साझेदार हैं लूट की पोटली में।' अखिलेश के इस बयान के बाद नीट परीक्षा को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी यह मामला उठाते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कटघरे में खड़ा किया है। यूपी कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में कहा कि कानपुर की एक होनहार छात्रा ने जब अपनी OMR शीट का मिलान किया तो उसके कुल 609 अंक बन रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि NTA की वेबसाइट पर महज 2 घंटे के भीतर ही उसका रिजल्ट बदल दिया गया। पार्टी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सीधे शब्दों में सवाल किया है कि देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा

स्कूटी योजना विवाद के बीच मंत्री असीम अरुण का नौकरशाही पर बड़ा बयान

उच्च शिक्षा में स्कूटी योजना की नीति पर ब्यूरोक्रेसी से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद अब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नौकरशाही के उस प्रसिद्ध 'स्टील फ्रेम' पर गंभीरता से पुनर्विचार करें, जिसे कभी प्रशासन की रीढ़ माना गया था। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की आकांक्षाओं के लिए लचीले कार्बन फाइबर की जरूरत है। असीम अरुणने रविवार को फेसबुक पर लंबी पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक सरकारी नीतियां सिर्फ फाइलों और कागजों में खूबसूरत दिखेंगी और जमीन पर लागू होने लायक नहीं होंगी, तब तक लोक कल्याण का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। नीति निर्माण में व्यावहारिकता का यह अभाव प्रशासनिक मशीनरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसका हल केवल आलोचना करने में नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ तक जाकर पूरे 'सिस्टम' को बदलने में है। मंत्री ने कहा कि यह सोचना होगा कि 'स्टील फ्रेम' में निष्पक्षता और ईमानदारी को सुरक्षित रखने वाले तंत्र प्रभावी हैं? क्या इसमें योग्य प्रतिभाओं को हम ला पा रहे हैं? आदर्श नौकरशाही की पहचान कुछ स्टार अधिकारियों से नहीं, बल्कि मजबूत सिस्टम से होती है। चुनाव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन इसका उदाहरण है जहां सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि लाखों कर्मियों के सामूहिक प्रयास को मिलता है। लेकिन जमीन की खरीद-फरोख्त, यातायात प्रबंधन, हाउस टैक्स संग्रह, नगर बसावट, आदि अनेक क्षेत्रों में सिस्टम आज भी कमजोर है।

लखनऊ हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सरकार से मांगा अनुपालन

यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जालौन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डॉ अरविंद त्रिवेदी को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध (अटैच) करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर आदेश दिया कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर संबंधित अफसर के खिलाफ अवमानना कानून के तहत आरोप निर्धारण समेत दंडित करने की कार्यवाही करेगा। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश डा अरविंद त्रिवेदी की अवमानना याचिका पर दिया। याची ने रिट कोर्ट के इसी 4 जून के आदेश का पालन न करने का दावा किया है। उधर, सरकारी वकील ने मामले में अनुपालन/ पक्ष पेश करने का हलफनामा दाखिल करने को 10 दिन का समय दिए जाने का आग्रह किया। जिसपर कोर्ट ने उक्त आदेश देकर अवमानना मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। दरअसल, 4 जून को रिट कोर्ट ने जालौन के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज के

प्रधाचार्य डाक्टर अरविंद त्रिवेदी को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध(अटैच) करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। रिट कोर्ट ने यह आदेश डा अरविंद त्रिवेदी की अन्य याचिका पर दिया था। इसमें याची ने बीती 26 मई के संबद्धता आदेश को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि वह जालौन के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत था। इसे निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया। याची ने इसे सेवा नियमों और कानून की मंशा के खिलाफ कहा था। उधर, सरकारी वकील ने कहा था कि स्टाफ की कमी व काम के दबाव की वजह से याचिकाकर्ता को निदेशालय से संबद्ध किया गया।

लखनऊ के ओमैक्स अपार्टमेंट में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़

सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमैक्स R - 2 अपार्टमेंट में बिना पुलिस सत्यापन के बढ़ी संख्या में किराएदारों के रहने का मामला सामने आया है। यहां 400 से अधिक फ्लैटों में किराएदार रह रहे हैं, लेकिन अधिकांश का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने अपार्टमेंट के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर का फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर लिया। ये लोग ऑनलाइन ऐप के जरिए फ्लैट की बुकिंग करते थे। पुलिस ने ओमैक्स R - 2 समेत आसपास के अन्य अपार्टमेटों की आरडब्ल्यूए और फ्लैट मालिकों को किराएदारों का पुलिस सत्यापन कराने के लिए नोटिस जारी किया है। क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम थाना की संयुक्त टीम ने हाल ही में ओमैक्स R-2 के 10 फ्लैटों में छापेमारी की थी। जांच के दौरान दो फ्लैटों में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के लिए संचालित फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से गुजरात निवासी पुनीत वर्मा और दीपेन पटेल को गिरफ्तार किया। इनके साथ कोलकाता निवासी मो. सोहेल, मो. शाहनवाज, मो. इमरान, मो. रियाज और सज्जाद हुसैन को भी दबोचा गया। आरोपी अमेरिका समेत अन्य देशों के नागरिकों को झांसा देकर ठगते थे। पीड़ितों से गिफ्ट कूपन और वाउचर खरीदवाए जाते थे। इन कूपन को विदेश में कैश कराया जाता था। इसके बाद रकम हवाला के जरिए भारत मंगवाकर गिरोह के सदस्यों में बांटी जाती थी। गिरोह के सरगना पुनीत कुमार वर्मा का भाई यश वर्मा और उसका दोस्त जिग्नेश अमेरिका में बैठे सुपर बॉस के सीधे संपर्क में हैं। दोनों फिलहाल फरार हैं।

लखनऊ मेट्रो ब्लू लाइन का काम शुरू, मूसाबाग में सॉयल टेस्टिंग शुरू

राजधानी लखनऊ में चारबाग से वसंतकुंज के बीच बनने वाली मेट्रो की ब्लू लाइन (फेज-1बी) के निर्माण की कवायद जमीन पर दिखने लगी है। एलिवेटेड स्टेशनों को तैयार करने वाली फर्म के इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ ने शनिवार को मूसाबाग में आधुनिक मशीनों के साथ 'जियो टेक्निकल इंवेस्टीगेशन' और 'सॉयल टेस्टिंग' का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ठीक एक महीने बाद इस रूट पर पिलर बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद की इस कार्यदायी फर्म को ठाकुरगंज से वसंतकुंज तक कुल 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने का टेंडर मिला है। शनिवार को टीम ने मूसाबाग में संभावित मेट्रो स्टेशन के पास बैरिकेडिंग लगाकर काम शुरू किया। मूसाबाग के बाद दुबग्गा में भी यही जांच की जाएगी। भौगोलिक स्थिति की जांच: जियो टेक्निकल इंवेस्टिगेशन के जरिए मूसाबाग मेट्रो स्टेशन के आसपास जमीन के नीचे मौजूद पाइप लाइनों, बिजली-इंटरनेट के तारों के जाल और अन्य बाधाओं (हर्डल्स) का पता लगाया जा रहा है। इन्हें चिह्नित करने के बाद ही पिलर के लिए खोदायी का सटीक स्पॉट तय होगा।

ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के विरोध में उतरे आरटीओ अधिकारी-कर्मचारी

आरटीओ में वाहनों के ट्रांसफर, पंजीकरण आदि सेवाओं की ऑटो अप्रूवल (स्वत: स्वीकृति) व्यवस्था लागू होने के विरोध में रविवार को लखनऊ सहित प्रदेशभर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिगुल फूंक दिया। अधिकारियों ने जहां मोटर व्हीकल एक्ट के पालन की मांग उठाई है। वहीं कर्मचारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ में बैठक कर सत्यापन व अप्रूवल का अधिकार विभाग के पास ही रहने देने की मांग उठाई। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन व कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी। वाहनों के ट्रांसफर, पंजीकरण सहित सभी कार्यों के लिए अभी तक आवेदकों को आरटीओ-एआरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है। शासन की ओर से इस व्यवस्था को बदला जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो अप्रूवल मोड के तहत उनके कार्य हो जाएंगे। इस व्यवस्था पर शासन की ओर से सोमवार को विचार-विमर्श के लिए बैठक भी बुलाई गई है। वहीं दूसरी ओर रविवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों व

कर्मचारियों ने ऑटो अप्रूवल व्यवस्था के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ की प्रांतीय वार्षिक आम सभा में इसके खिलाफ मोर्चा खोला गया। बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष संजय सिंह ने कहाकि शासन स्तर पर परिवहन विभाग की सभी सेवाओं को "ऑटो अप्रूवल" मोड पर डालने की तैयारी का हरस्तर पर विरोध किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑनलाइन स्तर पर सत्यापन और स्वीकृति(अप्रूवल) का अधिकार आरटीओ कार्यालय के पास ही रहना चाहिए। यदि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है तो भविष्य में न्यायालयों में विवेचना अधिकारियों को सूचनाएं देने के लिए डीलर्स को ही अधिकृत किया जाए।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण और जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष तथा पुलिस कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी थानों में दर्ज अभियोगों की समीक्षा की गई और गंभीर मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर जल्द चार्जशीट दाखिल करने पर जोर दिया गया। एसएसपी ने महिला अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने दुष्कर्म, पॉक्सोएक्ट और महिलाओं से जुड़े अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साथ ही, अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाकर दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। बैठक में शातिर और अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, गुंडा एक्ट के तहत जिलाबदर की कार्रवाई करने तथा माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। एसएसपी ने अवैध शराब, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थों की तस्करी और जुए के खिलाफ लगातार अभियान चलाने पर जोर दिया। चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर गश्त बढ़ाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से जनशिकायतों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर उनका विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आवेदकों से स्वयं संपर्क कर फीडबैक लेने और शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने, राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि विवादों की निगरानी करने तथा पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।

बातों में उलझाकर बदला एटीएम कार्ड, खाते से उड़ाए 62 हजार रुपये

उन्नाव में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बातों में उलझा कर पैसा निकालने गए व्यक्ति से एटीएम बदल लिया। इस दौरान एटीएम का पासवर्ड भी देख लिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कानपुर देहात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सात एटीएम कार्ड बरामद किया है। इसके खिलाफ औरैया, उन्नाव, फतेहपुर के थानों में मुकदमा दर्ज है। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी सरकारी अस्पताल के पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम स्थित है। इसी एटीएम से विजय पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल निवासी शक्ति नगर गंगा घाट 4 जून 2026 को पैसा निकालने के लिए गया था। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति विजय को बातों में उलझा लिया और एटीएम कार्ड बदल लिया। जिसने अलग-अलग समय पर ऑनलाइन शॉपिंग और कैश निकलने में कार्ड का इस्तेमाल किया। इस दौरान करीब 62 हजार रुपए का लेनदेन किया गया। विजय ने 17 जुलाई 2026 को गंगा घाट थाने में मुकदमा दर्ज करा कर न्याय की गुहार लगाई। गंगा घाट थाना उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी अपनी टीम के साथ विजय सिंह पुत्र विश्राम सिंह निवासी जरसेन थाना मूसानगर कानपुर देहात को गिरफ्तार किया। जिसके पास से सात एटीएम कार्ड जिसमें पांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक कार्ड बैंक ऑफ़ बड़ौदा और एक पंजाब एंड सिंद बैंक का एटीएम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि आरोपी के खिलाफ दिबियापुर औरैया, सदर कोतवाली उन्नाव, दो यूपी गैंगस्टर एक्ट के और फतेहपुर में मुकदमा दर्ज है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के माध्यम से जेल भेज रही है। मिली तहरीर के आधार पर गंगा घाट थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) में मुकदमा दर्ज किया था। बरामदगी के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 319(2), 317(2), 317(4) की वृद्धि की है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 4600 रुपए नगद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, हेड कांस्टेबल देवनारायण सिंह, कांस्टेबल लोकेंद्र यादव, कांस्टेबल प्रशांत कुमार शामिल थे।

उन्नाव में शराब ठेके पर हंगामा, ईंट-पत्थर चलने का वीडियो वायरल

उन्नाव के पीडी नगर स्थित एक शराब की दुकान पर युवक से मारपीट और रुपये छीनने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, शराब खरीदने पहुंचे एक युवक का महेंद्र, मन्नी और विकास नामक युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि तीनों ने युवक के साथ पहले अभद्रता की, फिर उससे रुपये छीन लिए और उसकी पिटाई कर दी। मारपीट से बचने के लिए युवक किसी तरह मौके से भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक के भागने के बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने शराब की दुकान पर ईंट-पत्थर फेंककर हंगामा किया, जिससे दुकान पर मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी फरार हो गए। शराब दुकान के सेल्समैन आकाश ने आरोप लगाया कि ये युवक आए दिन दुकान पर आकर विवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि ये गांवों से रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों को रोककर उनसे झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और रुपये भी छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, उन पर लोगों को जबरन शराब पिलाने का दबाव बनाने का भी आरोप है। सेल्समैन के अनुसार, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी नशे की हालत में होने के कारण उन्हें समझाकर घर भेज दिया गया। इस बार भी अस्पताल चौकी प्रभारी अंजनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है।

पुल का एप्रोच मार्ग गंगा नदी की कटान में तीन साल पहले बह गया

बीघापुर क्षेत्र में गढ़ेवा डोमनपुर-कानपुर नगर मार्ग व पुल से प्रभावित छह लाख आबादी को जल्द ही राहत होगी। सेतु निगम व लोक निर्माण विभाग ने पुल की सड़क के लिए 88 करोड़ रुपये व पुल के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। 1300 मीटर बढ़कर अब यह पुल 1000 मीटर के स्थान पर 2300 मीटर हो जाएगा। यह पुल गढ़ेवा की तरफ 800 मीटर व कानपुर की तरफ 500 मी बढ़ेगा। इसके बाद भी दोनों तरफ बस्ती तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आगे का मार्ग 88 करोड़ से लोक निर्माण विभाग चौड़ीकरण कराएगा। इस कवायद के साकार होते ही कानपुर व जनपदीय क्षेत्र की जनता आसानी से कानपुर व उन्नाव में आवागमन कर सकेगी। बीघापुर क्षेत्र में गढ़ेवा डोमनपुर-कानपुर नगर मार्ग पर गढ़ेवा के पास गंगा नदी में बना पुल का एप्रोच मार्ग गंगा नदी की कटान में तीन साल पहले बह गया था। इसके बाद आज तक एप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। एप्रोच मार्ग न होने के कारण पुल हवा में लटका है। अब बरसात शुरू हो गई। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रवासी चिंतित हैं।

100 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर फंदे से लटका युवक

मैं जो भी कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नजदीकी युवती के लिए कर रहा हूं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर यह पोस्ट डालकर असोहा क्षेत्र दाऊखेड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक ने चचेरी बहन की ससुराल दऊ के पास से निकली हाइटेंशन विद्युत लाइन के पोल में लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर गमछे के सहारे फंदा लगा जान दे दी।चचेरे बहनोई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मदद से शव को पोल से नीचे उतरवाया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ जांच की। हालांकि अभी तक स्वजन ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। असोहा क्षेत्र के गांव दाऊखेड़ा निवासी महेश रावत का 22 वर्षीय बेटा ओमकार आटो चालक था। चार दिन पूर्व अपनी चचेरी बहन आरती की ससुराल क्षेत्र के ही गांव दऊ आया था। शनिवार दोपहर लगभग दो बजे वह घर से घूमने जाने की बात कहकर निकला था। देर शाम तक वापस घर न लौटने पर आरती सहित अन्य स्वजन ने खोजबीन की पर ओमकार का कहीं पता नहीं चल सका। रविवार सुबह लगभग सात बजे पड़ोसी गांव दरसवां निवासी चचेरे बहनोई रंजीत ने गांव के बाहर से निकली हाईटेंशन विद्युत लाइन के पोल में लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर ओमकार का शव गमछे के सहारे लटका देखा। जानकारी पर चचेरी बहन आरती सहित उसके स्वजन को दी। मौके पर पहुंचे स्वजन शव देख बेहाल हो गए। स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मदद से लगभग पांच घंटे बाद पोल से शव को नीचे उतारा। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि ओमकार की गांव की ही गैर बिरादरी की एक युवती से मित्रता थी। कुछ दिन पूर्व उसी युवती के स्वजन ने पुलिस से शिकायत भी की थी। जिस पर थाने में दोनों में सुलह समझौता हो गया था। इसी बात से दुखी होकर उसने यह कदम उठा लिया। वहीं ओमकार की इंस्टाग्राम आईडी पर उसके द्वारा डाली गई एक एक पोस्ट भी प्रचलित हो रही है। उस पोस्ट में उसने लिखा है कि मैं जो भी कर रहा हूं अपनी मर्जी से युवती के लिए कर रहा हूं। साथ ही उसी पोस्ट में पोल के ऊपर खड़ा होकर उसने एक वीडियो भी बनाया है।

उन्नाव में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत, मौसम हुआ सुहावना

उन्नाव में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में रविवार दोपहर दो बजे पुलिस परिवार के बच्चों के लिए नवनिर्मित चिल्ड्रेन पार्क का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जय प्रकाश सिंह ने फीता काटकर विधिवत पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात कानून-व्यवस्था और जनसेवा में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में उनके परिवारों, विशेषकर बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में विकास के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। इस पार्क का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि पुलिस परिवार के बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का बेहतर अवसर मिल सके। यह पार्क बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, क्षेत्राधिकारी हसनगंज तेज बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर विनी सिंह, क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ हर्ष मोदी और क्षेत्राधिकारी यातायात अजय कुमार सिंह सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका, रियायती बिजली दर पर संकट

उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने लाखों उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बढ़ाकर 1200 यूनिट से कम खपत करने वालों को भी लाइफलाइन टैरिफ से वंचित कर दिया। उपभोक्ता परिषद ने इसे टैरिफ आदेश के खिलाफ बताते हुए नियामक आयोग में याचिका दायर कर राहत की मांग की।

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार 1200 यूनिट सालाना से कम बिजली खपत करने वालों को लाइफलाइन टैरिफ यानी रियायती दर का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियों ने स्वीकृत लोड बढ़ने के आधार पर इन्हें भी इस सुविधा से बाहर कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को दोहरी मार पड़ी है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस व्यवस्था को टैरिफ आदेश की भावना के विपरीत बताया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि टैरिफ आदेश में साफ प्रावधान है कि पूरे वित्तीय वर्ष में खपत 1200 यूनिट से अधिक होने पर ही लाइफलाइन श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। लोड बढ़ने को आधार बनाकर रियायती दर छीनना गलत है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता की सालाना खपत मात्र 1000 यूनिट है लेकिन लोड 1 किलोवाट हो गया तो उसे रियायती दर से वंचित करना उचित नहीं। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जुलाई माह में ही करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बढ़ाया है। इनमें लगभग 15 लाख वे उपभोक्ता शामिल हैं जिनके पास पहले 1 किलोवाट का कनेक्शन था और वे लाइफलाइन टैरिफ का लाभ ले रहे थे। परिषद का दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी सालाना खपत 1200 यूनिट से कम है, फिर भी लोड बढ़ने के कारण उन्हें सामान्य दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर 7 जुलाई को राज्य विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व की याचिका दायर की गई है। उपभोक्ता परिषद ने आयोग से कानूनी पड़ताल कर इस आदेश की समीक्षा करने और प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। परिषद ने विद्युत वितरण संहिता 2005 का भी हवाला दिया है। राज्य में करीब 90 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर लगे हैं, जबकि लगभग 3 करोड़ उपभोक्ता अभी भी पुराने मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिषद का कहना है कि बिना स्पष्ट कानूनी प्रावधान के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं वाली व्यवस्था को सामान्य मीटर वालों पर लागू नहीं किया जा सकता। यह पूरा मामला आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। खासकर ग्रामीण और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई दरें उनके मासिक खर्च को प्रभावित करेंगी। बिजली कंपनियों का कहना है कि लोड बढ़ाने से सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन उपभोक्ता संगठन इसे बिना पूर्व सूचना और सहमति के एकतरफा कदम मान रहे हैं।

गोंडा में अवैध दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़, 1.13 करोड़ की दवाएं बरामद

गोंडा में नशीली और अवैध दवाओं के कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने तीन अवैध गोदामों पर छापा मारकर करीब 1.13 करोड़ रुपये की दवाएं बरामद की हैं। इनमें ट्रामाडोल इंजेक्शन, कोडीन सिरप और अल्प्राजोलम जैसी नशीली दवाएं शामिल हैं। कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जबकि मुख्य आरोपी फरार है, उसकी तलाश जारी है। प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान के तहत गोंडा में अवैध और नशीली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और पुलिस की संयुक्त टीम ने तीन दिनों तक लगातार छापेमारी कर तीन अवैध गोदामों को सीज कर दिया। इन गोदामों से करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपये की दवाएं बरामद हुई हैं। यह कार्रवाई 16 से 18 जुलाई के बीच बरियार पुरवा, सोनार गली और बड़गांव इलाके में की गई। छापेमारी में प्रदेश के नौ जिलों से आए औषधि निरीक्षकों के साथ स्थानीय पुलिस भी शामिल रही। अधिकारियों को पहले से सूचना मिली थी कि इलाके में बिना लाइसेंस दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। जांच के दौरान टीम सबसे पहले गोंडा-बलरामपुर मार्ग पर स्थित अमन फार्मास्युटिकल्स पहुंची। लेकिन फर्म अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिली। वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा था। इसके बाद टीम संचालक अमन कसौधन के घर पहुंची। जहां पूछताछ में उसके भाई शिवम कसौधन ने स्वीकार किया कि दोनों भाई दवाओं का कारोबार करते हैं।

संतकबीर नगर में 300 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर बारिश से ढहा

संतकबीर नगर के धनघटा क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण 300 साल पुराने बाबा बैजूनाथ मंदिर अचानक भरभराकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मंदिर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह वही मंदिर है जहां 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर दर्शन-पूजन किया था और इसके संरक्षण व पर्यटन विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। मंदिर गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने इसके पुनर्निर्माण की मांग उठाई है। बाबा बैजूनाथ मंदिर हाल ही में उस समय चर्चा में आया था, जब 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में दर्शन-पूजन किया था। धनघटा और खजनी विधानसभा क्षेत्र की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर की ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए यहां पूजा-अर्चना की थी। इस दौरान उन्होंने मंदिर के संरक्षण और पर्यटन विकास को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए थे। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर 300 साल पुराना था, लगातार हो रही बारिश के कारण इसकी संरचना कमजोर हो गई थी। पहले दीवारों में दरारें आईं और उसके बाद अचानक मंदिर का बड़ा हिस्सा गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके जल्द पुनर्निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था और पुरानी विरासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए जल्द कदम उठाए जाने चाहिए।

संतकबीर नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार का इनामी तस्कर गिरफ्तार

संतकबीर नगर जिले की पुलिस ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50 हजार के इनामी तस्कर भट्टू अली को गिरफ्तार कर लिया। यह कारवाई धनघटा और महुली पुलिस की संयुक्त टीम ने की और वांछित आरोपी समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 23 किलो 810 ग्राम गांजा, एक बिना नंबर की बोलेरो पिकअप, एक अवैध तमंचा, दो कारतूस, दो मोबाइल फोन और 800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने इस गुड वर्क पर धनघटा और महुली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भुट्टू अली पुत्र नूर मोहम्मद शाह, बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले का निवासी है। वह धनघटा और महुली थाने में दर्ज चोरी के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। DIG बस्ती ने इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार के इनाम की घोषणा की थी, जानकारी के मुताबिक आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 12 मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी की सूचना देते हुए SP ने बताया कि बिना नंबर की एक पिकअप में सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति अशरफपुर बाजार में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही धनघटा पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को देखकर चालक बैरियर तोड़ते हुए सिरसी की ओर भाग निकला। इसकी सूचना मिलते ही महुली पुलिस ने भी घेराबंदी कर दी। बदमाश दोनों तरफ से घिरने पर भागने लगे, इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। हादसे में चालक के पैर में चोट आने पर उसे सीएचसी हैंसर बाजार भेजा गया। धनघटा थाने में बीएनएस, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में नया प्राथमिकी दर्ज किया गया है। SP ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कबाड़ और नए पाट्र्स जोड़कर बिना नंबर की पिकअप तैयार कराई थी तथा पहचान छिपाने के लिए इंजन और चेसिस नंबर भी घिसकर मिटा दिए थे।